P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-9* ISSUE-5* January- 2022
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारतीय कृषि विकास की आवश्यकताः दूसरी हरित क्रान्ति

Need For Indian Agriculture Development: Second Green Revolution

Paper Id: 15615 Submission Date: 10/01/2022, Date of Acceptance: 22/01/2022, Date of Publication: 24/01/2022

संगीता सिंघल
एसोसिएट प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग,
एस0डी0 कॉलेज,
मुजफ्फरनगर,
उत्तरप्रदेश, भारत

सारांश / Abstract

स्वतंत्रता के बाद देश में कृषि विकास के लिए पहला संगठित प्रयास 1960-61 में शुरू किया गया। 1960-70 के दशक के मध्य में नयी कृषि विकास रणनीति अर्थात् अच्छे बीज, उर्वरक, पानी, तकनालाजी का प्रयोग करके कृषि उत्पादकता को बढ़ाने पर बल दिया गया, जिसे हरित क्रान्ति के रूप में जाना गया। हरित क्रान्ति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता विशेषक गेहूँ व चावल के उत्पादन में आशा से अधिक वृद्धि हुई। कुल मिलाकर पहली हरित क्रान्ति से देश में खाद्यान्न उत्पादन न केवल दुगुना हुआ बल्कि सिंचाई, कृषि उत्पादों के रख-रखाव, उनके विपणन, नई बीजों के उत्पादन, उर्वरकों के प्रयोग, कृषि संबंधी शोध अनुसंधानों इत्यादि के क्षेत्र में भारत ने तीव्र प्रगति की।

हाल ही के वर्षों में यह महसूस किया जा रहा है कि अधिक उपजाऊ किस्म के बीज, पानी उर्वरक, तकनीकी अपनी सम्भाव्य क्षमता का पूरा प्रयोग कर चुकी है और ऐसे बिन्दु पर पहुँच गयी है कि ह्रासमान प्रत्याय (Diminishing return) की अवस्था आरम्भ हो गयी है। इसी स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए जनवरी 2006 में, भारतीय कृषि में बहुमुखी विकास हेतु, पूर्व राष्ट्रीय ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 9-10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु देश में दूसरी हरित क्रान्ति की आवश्यकता बताई थी। इन्ही स्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय किसान आयोग ने कृषि के मूलभूत क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधार लाने के लिए वर्ष 2006-07 को कृषि नवीकरण के रूप में घोषित किया।

कृषि क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन सकारात्मक या नकारात्मक समग्र अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव डालता है। आज देशभर में किसान आत्महत्याएँ कर रहे है। देश की 121 करोड जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों एवं बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करना सरकार का कर्तव्य है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी अधिकतर पंचवर्षीय योजनाएं कृषि के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल हुई है वास्तव में देश में कृषि को सापेक्षतः कम महत्व दिया गया और उद्योगों एवं सेवाओं को अधिक प्राथमिकता दी गई। भारत आज एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है, एक ओर भारत उभर रहा है और इसका विनिर्माण और सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और वित्तीय बाजार में भी तेजी की लहर मजबूत होती चली आ रही है लेकिन कृषि क्षेत्र में अंधेरा गहरा होता जा रहा है। अतः दूसरी हरित क्रान्ति को देश में तेजी से लाना होगा और इसमें देश के प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता को भविष्य में बनाए रखकर, कृषि उत्पादन व उत्पादिता को बढाना होगा। इसके लिए कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण को भी सक्रिय बनाकर कृषि को एक लाभप्रद व्यवसाय बनाना ही होगा और परम्परागत खेती के साथ-साथ भारत को औद्योगिक खेती, संयुक्त खेती व संरक्षणवादी खेती आदि का उपयोग करना होगा ताकि वह प्रगतिशील कृषि का नया मार्ग ग्रहण कर सके।

The first organized effort for agricultural development in the country after independence was started in 1960-61. In the mid 1960s-70s, emphasis was laid on increasing agricultural productivity by using new agricultural development strategy i.e. good seeds, fertilizers, water, technology, which came to be known as Green Revolution. As a result of the Green Revolution, the productivity of crops, especially the production of wheat and rice, increased more than expected. Overall, the first Green Revolution not only doubled the production of food grains in the country, but also made rapid progress in the field of irrigation, maintenance of agricultural products, their marketing, production of new seeds, use of fertilizers, research related to agriculture, etc. In recent years it is being realized that more fertile varieties of seeds, water fertilizers, technology have fully utilized their potential and have reached such a point that the stage of diminishing return has begun. Is. Expressing concern over this situation, in January 2006, for all-round development in Indian agriculture, former national APJ Abdul Kalam had told the need of second green revolution in the country to achieve the target of 9-10 percent annual growth in the Indian economy. Keeping these conditions in mind, the National Commission for Farmers has declared the year 2006-07 as Agricultural Renewal to bring structural reforms in the basic areas of agriculture.

Any change in the agricultural sector has a positive or negative multiplier effect on the overall economy. Farmers are committing suicides all over the country today. It is the duty of the government to supply food grains and basic needs for the country's 121 crore population. Unfortunately, most of our Five Year Plans have failed to achieve the

set goals of agriculture. In fact, relatively less importance was given to agriculture in the country and more priority was given to industries and services. India is passing through a dangerous phase today. On the one hand India is emerging and its manufacturing and services sector is growing rapidly and the wave of bullishness in the financial market is also getting stronger but the darkness is deepening in the agriculture sector. Therefore, the second green revolution will have to be brought fast in the country and in this, by maintaining the quality of natural resources of the country in the future, agricultural production and productivity will have to be increased.

For this, by activating capital formation in the agriculture sector, agriculture has to be made a profitable business and along with traditional farming, India will have to use industrial farming, joint farming and protectionist farming etc. so that it can adopt a new path of progressive agriculture. Can you

मुख्य शब्द हरित क्रान्ति, खाद्यान, उत्पादकता, नई कृषि तकनीक, कृषि नवीकरण।
Keywords Green Revolution, Food Grains, Productivity, New Agricultural Technology, Agricultural Renewal

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के आर्थिक जीवन का लगभग प्रत्येक पहलू कृषि क्षेत्र द्वारा प्रभावित होता है। राष्ट्रीय आय का 14.2 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर करती है। भारत के उद्योग, कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल की बिक्री के लिए, कृषि क्षेत्र पर निर्भर करते है। हमारी योजनाओं की सफलता काफी हद तक कृषि विकास एवं प्रगति पर निर्भर करती है। भारत में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए पहला संगठित प्रयास 1960-61 में ''गहन कृषि जिला कार्यक्रम'' के लिए चुने गए सात जिलों के लिए पाइलट परियोजना के रूप में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को ऋण, अच्छे बीज, खाद, औजार आदि उपलब्ध कराना एवं केन्द्रीय प्रयासों द्वारा दूसरे क्षेत्रों के लिए गहन खेती का ढ़ाँचा तैयार करना था। 1964-65 से इसी प्रकार का एक दूसरा कार्यक्रम ''गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम'' IAAP देश के अन्य भागों में लागू किया गया। यह दोनों कार्यक्रम "IADP" तथा "IAAP" गहन कृषि से सम्बन्धित थे। इस प्रकार भारत में हरित क्रान्ति की शुरूआत छठे दशक के मध्य में, कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि और ऊँची उपज वाले बीजों (High Yielding Varities or Seeds - HYVs) एवं रसायनिक खादों व नई तकनीक के प्रयोग के फलस्वरूप हुई। हरित क्रान्ति से देश में खाद्यान्न उत्पादन न केवल दुगुना हुआ बल्कि सिंचाई कृषि उत्पादों के रख-रखाव, उनके विपणन, नई बीजों के उत्पादन, उर्वरक के प्रयोग, कृषि सम्बन्धी शोध अनुसंधानों इत्यादि के क्षेत्र में भारत में तीव्र प्रगति की। इस कृषि विकास रणनीति को अपनाने के कारण फसलों के आधीन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई साथ ही फसलों की उत्पादकता विशेषतः गेहूँ चावल के उत्पादन में आशा से अधिक वृद्धि हुई जोकि तालिका से स्पष्ट है।

तालिका

खाद्यान्नों के उत्पादन की प्रगति (लाख टन)

	1960-61	1990-91	2012-13	2013-14	2017-18	2018-19
चावल	350	750	1040	1070	1129-2	1156
गेहूँ	110	550	940	960	997	991
मोटे अनाज	230	320	400	430	470	426
a) कुल अनाज	690	1620	2380	2460	2596	2573
b) कुल दालें	130	140	190	190	252	240
c) कुल खाद्यानन (a+b)	820	176	2570	2650	2848	2813

सोत्रः- Ministry of Agriculture Govt. of India 2009, आर्थिक समीक्षा 2014-15 तथा प्रतियोगिता दर्पण 2019-20

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चावल का उत्पादन जो 1960-61 में 350 लाख टन था बढकर 2018-19 में 1156 लाख टन हो गया। गेहूँ का उत्पादन जो 1960-61 में 110 लाख टन था यह बढ़कर 2018-19 में 991 लाख टन हो गया। अन्य मोटे अनाजों और दालों में कोई विशेष वृद्धि नही हुई। हरित क्रान्ति की आरम्भिक सफलता के बाद यह आशा की जाती थी कि खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति बनी रहेगी। इसलिए खाद्य आयात बन्द कर दिए गए और काफी अच्छी मात्रा में बफर-स्टॉक एकत्र कर लिए गए। परन्तु 1972-73 में सूखा पड़ने के कारण यह स्थिति कायम न रह सकी। तालिका से यह भी स्पष्ट है कि हरित क्रान्ति ने दालों के उत्पादन पर कोई प्रभाव नही डाला। अतः हरित क्रान्ति केवल अनाजों मुख्यतः गेहूँ चावल तक ही सीमित रही। नयी कृषि त्कनीकी को सफलतापूर्वक अपनाने के कारण 1965-2013 की अवधि में चावल की फसल के आधीन क्षेत्रफल में वार्षिक वृद्धि दर केवल 0.35 प्रतिशत थी जबकि गेहूँ के आधीन क्षेत्रफल में यह 1.71 प्रतिशत थी। कुल कृषि आधीन क्षेत्रफल में गेहूँ का भाग 8.5 प्रतिशत से बढ़कर 17.7 प्रतिशत हो गया। सिंचाई आधीन क्षेत्रफल में गेहूँ का भाग 15 प्रतिशत से बढ़कर 27 प्रतिशत हो गया।

नयी कृषि तकनीकी को अपनाने से कृषि रोजगार की वृद्धि हुई, क्योंकि बहुफसलीकरण (Multiple cropping) अपनाया गया। इसके साथ ही कृषि मशीनरी के विस्तृत प्रयोग से कृषि श्रम का विस्थापन भी हुआ। यह भी विचारणीय तथ्य है कि भारतीय कृषि संवृद्धि जो 1960 के दशक के मध्य लगातार बढ़ रही थी, 1990 के दशक के मध्य में कृषि संवृद्धि दर में लम्बी अवधि तक गिरावट का रूख रहा और 1997-98 से 2004-05 के बीच कृषि क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद (agricultural GDP) में वृद्धि की दर मात्र 2.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही जो 1981-82 से 1996-97 के बीच प्राप्त की गई, 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बहुत कम थी।

इस कृषि क्रान्ति का प्रसरण प्रभाव भी कमजोर रहा तथा इसके अन्तर्गत प्रयुक्त कृषि यन्त्रीकरण से श्रम विस्थापन को बढावा मिला। डॉ0 वी0के0 आर0वी0राव के अनुसार "यह बात सर्वविदित है कि तथाकथित हरित क्रान्ति, जिसने देश में खाद्यान्न उत्पादन बढाने में सहायता दी है, के साथ ग्रामीण आय में असमानता बढी है, बहुत से छोटे किसानों को अपने काश्तकारी अधिकार छोड़ने पडे है और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक तनाव बढ़े हैं। इस हरित क्रान्ति से केवल बड़े फॉर्मों और बड़े किसानों को ही लाभ हुआ क्योंकि 62 प्रतिशत सीमान्त जोतें जिनके अधीन संकार्य क्षेत्रफल का 17 प्रतिशत था और 31 प्रतिशत छोटी जोतें जिनके अधीन 55 प्रतिशत संकार्य क्षेत्र (Operational Area) था, इस क्रान्ति के लाभ से वंचित रही। इसके अतिरिक्त इस क्रान्ति ने किसानों को बाजार प्रेरित बना दिया। किसान आदानों के सम्भरण के लिए और अपने उत्पाद की मांग के लिए बाजार पर अधिक निर्भर हो गए है। इसके साथ-साथ नयी तकनीक के प्रयोग से किसानों की नकद आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है। उनकी कृषि उधार की मांग भी बढ गई है। हरित क्रान्ति के आरम्भिक वर्षों में निजी निवेश के रूप में, सिंचाई पम्पों, कुंओं, टै[a]क्टरों आदि में काफी उन्नति हुई, तत्पश्चात् कृषि में निजी निवेश में गिरावट आयी। चिन्ता का विषय है कि कृषि में निजी निवेश विशेषकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संकेन्द्रित है और देश के अन्य भागों में यह बहुत कम है। इसी प्रकार कृषि में सार्वजनिक निवेश की स्थिति भी असंतोषजनक है। हाल ही के वर्षों में यह महसूस किया जा रहा है कि अधिक उपजाऊ किस्म के बीज, पानी उर्वरक, तकनीकी अपनी सम्भाव्य क्षमता का पूरा प्रयोग कर चुकी है और ऐसे बिन्दु पर पहुँच गयी है कि ह्रासमान प्रत्याय (Diminishing return) की अवस्था आरम्भ हो गयी है। इसी स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए जनवरी 2006 में, भारतीय कृषि में बहुमुखी विकास हेतु, पूर्व राष्ट्रीय ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 9-10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु देश में दूसरी हरित क्रान्ति की आवश्यकता बताई थी।

अध्ययन का उद्देश्य

भारतीय कृषि, सकल घरेलु उत्पाद (G. D. P.) में लगभग 17 प्रतिशत योगदान के साथ दो तिहाई जनसँख्या को आजीविका प्रदान कर रही है। इस शोध का मुख्य उद्देष्य, सकल घरेलु उत्पाद में घटते कृषि योगदान को बढ़ाना है जिससे घटती कृषि योग्य भूमि के उपरान्त भी, नयी कृषि रणनीति के साथ कृषि उत्पादन व किसानो की आय में वृद्धि हो, और देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो।

साहित्यावलोकन

सी0एच0 हनुमन्त राव के अनुसार 1990-91 से बाद की अवधि में कृषि संवद्धि दर में गिरावट के मुख्य कारण थे- सार्वजनिक निवेश और योजना परिव्यय में गिरावट होना, कृषि आंगतो का अंसतुलित उपयोग होना तथा कृषि व संबद्ध गतिविधियों को प्रदान किए जाने वाले मध्यकालिक/दीर्घकालिक प्रत्यक्ष ऋणों की वार्षिक संवृद्धि दर जो 1980 के दशक में 11.5 प्रतिशत थी, 1990 के दशक में कम होकर 9.7 प्रतिशत रह जाना इत्यादि। इस प्रकार हरित क्रान्ति की सफलताओं के साथ कुछ विफलताएँ भी देखी गयी जैसे इस कृषि रणनीति के कारण भारत में पूंजीवादी खेती का विकास हुआ, यह केवल गेहूँ व चावल की फसल तक ही सीमित रही तथा इसका लाभ बड़े भूस्वामियों को ही मिला, क्योंकि भारी निवेश करना, भारत में छोटे व मध्यम श्रेणी की किसानों की क्षमता से बाहर है। भारत में केवल 6 प्रतिशत बड़े किसानों के पास कुल भूमि का 40 प्रतिशत है और केवल वही, नलकूप पम्पिंग सेट, उर्वरक और भारी मशीनरी के रूप में भारी निवेश कर रहे है।

डॉ0 कलाम ने वर्ष 2020 तक देश में खाद्यान्न उत्पादन को दुगुना करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था कि इस मुहिम में वर्तमान में प्रयोग हो रही 17 करोड हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 10 करोड हैक्टेयर

भूमि ही पर्याप्त साबित हो सकती है किन्तु यह तभी सम्भव है जब हम कृषि की नवीनतम तकनीक का प्रयोग करें। साथ ही कृषि पूर्व तथा कृषि के बाद की प्रक्रियाओं तथा कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक ढंग से भण्डारण पर भी ध्यान देना होगा। इन्ही स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2006-07 में कृषि में बहुमुखी विकास हेतु कृषि के मूलभूत क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधार लाने हेतु कृषि नवीनीकरण वर्ष घोषित किया।

राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष डॉ0 एम0एस0 स्वामीनाथन ने कृषि नवीकरण के पांच अंगों का उल्लेख किया जिनमें भूमि स्वास्थ्य में सुधार, जल संरक्षण और पानी का पोषणीय एवं समतावादी प्रयोग, क्षमतानुसार उधार तक पहुँच और फसल एवं बीमा सुधार, उचित तकनालाजियों का विकास एवं प्रसारण और उन्नत अवसर, कृषि उत्पादन के विपणन के लिए आधार संरचना और विनियमन।

1. भूमि स्वास्थ्य सुधार के लिए भूमि में समाप्ति एवं व्यष्टि पोषकों द्वारा और भूमि की भौतिकी एवं सूक्ष्म जैविकी उन्नत करनी होगी।
2. जलसंरक्षण द्वारा पानी की सुरक्षा करनी होगी और पानी के कुशल एवं समतापूर्ण प्रयोग लिए ग्राम सभाओं को "पानी पंचायती" के रूप में सशक्त करना होगा। अतः एक टिकाऊ जल संग्रहण प्रणाली स्थापित करनी होगी और इस जल संरक्षण द्वारा शुष्क खेती की ओर ध्यान देना होगा।
3. छोटी जोतों की उत्पादिता को बढाने और किसानों की आत्महत्याएं समाप्त करने हेतु हमें ऋण सुधारों के बारे में पहल करनी होगी अर्थात् ब्याज दरों में कटौती करनी होगी इसके साथ ही सहकारी ऋण व्यवस्था को पुर्नजीवित करना होगा। प्राकृतिक विपदाओं का मुकाबला करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को कृषि जोखिम निधि (Agriculture Risk Fund) स्थापित करनी चाहिए ताकि किसानों को राहत दी जा सकें।
4. कृषि वैज्ञानिकों को नयी किस्म के बीजों और तकनालाजियों के निष्पादन को प्रति एकड़ शुद्व आय के रूप में व्यक्त करना चाहिए, न कि प्रति एकड़ उत्पादिता के रूप में। आयोग का यह सुझाव भी है कि कृषि विकास केन्द्रों में एक नया विभाग फसल उपरान्त तकनालाजी का स्थापित करना चाहिए इसके लिए बहुत सी प्रदर्शनियों को खुश्क खेती क्षेत्रों में आयोजित करने की जरूरत है जहां बाजरा, दाल, तिलहनों और रूई की फसल उगाई जाती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण फॉर्म विज्ञान प्रबन्धकों का एक संवर्ग तैयार करना चाहिए। इसके साथ ही एक जोखिम स्थिरीकरण निधि और एक किसान केन्द्रित न्यूनतम समर्थन कीमत तय करनी चाहिए। आज इस क्षेत्र में विशेष प्रयास किए जा रहे है। ग्रामीण बैंको द्वारा किसानों को कृषि ऋण के साथ-साथ बीमा भी उपलब्ध कराया जा रहा है तथा कर्ज में डूबें किसानों को बड़ी राहत देने का कार्य भी सरकार कर रही है। भूमि प्रयोग परामर्श केन्द्र किसान कॉल सैन्टर, जोखिम स्थिरीकरण, कृषि जोखिम निधी ऋण एवं बीमा उपलब्धता जैसी योजनाओं को शुरू कर कृषि क्षेत्र में नई ऊँचाईयों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। क्यांेकि पहली क्रान्ति की विफलताओं को देखते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी दूसरी हरित क्रान्ति का आहवान किया था क्योंकि इन्होनें पहली क्रान्ति की विफलता के दो कारण बताए पहला इससे खुष्क भूमि खेती (Dryland farming) का कोई लाभ नही हुआ। दूसरा यह आकार तटस्थ (Scale neutral) नही था और इससे केवल बडे फार्मो और बडे किसानों को ही लाभ हुआ।

निष्कर्ष

आज, कृषि क्षेत्र में दूसरी हरित क्रान्ति लाने की जरूरत से इंकार नही किया जा सकता है क्योंकि कृषि क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन सकारात्मक या नकारात्मक समग्र अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव डालता है। आज देशभर में किसान आत्महत्याएँ कर रहे है। देश की 121 करोड जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों एवं बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करना सरकार का कर्तव्य है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी अधिकतर पंचवर्षीय योजनाएं कृषि के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल हुई है वास्तव में देश में कृषि को सापेक्षतः कम महत्व दिया गया और उद्योगों एवं सेवाओं को अधिक प्राथमिकता दी गई। भारत आज एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है, एक ओर भारत उभर रहा है और इसका विनिर्माण और सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और वित्तीय बाजार में भी तेजी की लहर मजबूत होती चली आ रही है लेकिन कृषि क्षेत्र में अंधेरा गहरा होता जा रहा है। अतः दूसरी हरित क्रान्ति को देश में तेजी से लाना होगा और इसमें देश के प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता को भविष्य में बनाए रखकर, कृषि उत्पादन व उत्पादिता को बढाना होगा। इसके लिए कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण को भी सक्रिय बनाकर, कृषि को एक लाभप्रद व्यवसाय बनाना ही होगा और परम्परागत खेती के साथ-साथ भारत को औद्योगिक खेती, संयुक्त खेती व संरक्षणवादी खेती आदि का उपयोग करना होगा ताकि वह प्रगतिशील कृषि का नया मार्ग ग्रहण कर सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *एल0एन0 कोली "भारतीय आर्थिक समस्याएँ"।*
2. *लक्ष्मी नारायण नाथूराम का "भारतीय अर्थव्यवस्था: बदलता परिदृश्य।"*
3. *वी0के0पुरी, एस0के0पुरी "भारतीय अर्थव्यवस्था।"*
4. *दत्त एवं सुन्दरम "भारतीय अर्थव्यवस्था।"*
5. *प्रतियोगिता दर्पण "अतिरिक्तोक" भारतीय अर्थव्यवस्था, 2019।*
6. *डॉ0 आर0के0 गोविल, डॉ0 एस0 दयाल "कृषि अर्थशास्त्र"।*
7. *टी0आर0जैन "भारतीय आर्थिक समस्याएँ"।*
8. *डॉ0 जे0सी0 पन्त एवं डॉ0 जे0पी0 मिश्रा "भारतीय आर्थिक समस्याएं।'*